पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 01 अंक : 04 फरवरी 2021 परस्पर संपर्क हेतु

पेयजल प्रबंधन में ग्रामवासियों की भागीदारी

पलानीमाल गांव के लोगों ने जलकर का भुगतान कर नल-जल योजना को सफल बनाने की मिसाल प्रस्तुत की

खंडवा। गांव के संसाधनों और सुविधाओं के प्रबंधन और संचालन में ग्रामवासियों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्वशासन की दिशा में इसे एक जरूरी कदम माना जाता है।

हमारी ग्राम पंचायतों में स्वशासन की स्थिति का आकलन पेयजल प्रबंधन और संचालन को देखकर किया जा सकता है। क्योंकि नल—जल योजना आधारित पेयजल व्यवस्था तभी सफल हो सकती है, जबकि लोग उसमें भागीदारी करें जलकर देकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह देखा गया है कि कई ग्राम पंचायतों में नल—जल योजना इसलिए सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां लोग जलकर की राशि नहीं चुकाते।

खण्डवा जिले की ग्राम पंचायत पलानीमाल की भी यही स्थिति रही है। नल—जल योजना के बावजूद लोग जल संकट का सामना करने को विवश थे। इस दशा में समर्थन ने जलकर के प्रति लोगों को जिम्मेदारी का अहसास

कराने एवं स्थानीय स्वशासन की मूल भावना को जमीनी स्तर पर साकार करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप आज यहां नल—जल योजना से लोगों को पानी मिल रहा है। पलानीमाल में समर्थन के कार्यकर्ता द्वारा गांव में नल—जल योजना के प्रबंधन पर चर्चा की गई। उनसे पूछा गया कि यहां लाखों रूपए खर्च करके नल—जल योजना लागू की गई। इसके बावजूद यह बंद क्यों है? लोगों का कहना था कि उन्हें निःशुल्क यानी बगैर जलकर चुकाए पानी मिलना चाहिए। इस पर चर्चा गई कि यदि लोग जलकर नहीं चुकाएं तो बिजली का खर्च तथा मेन्टेनेन्स का खर्च कहां से होगा? यदि हम अपने घर में पानी की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो उसका टैक्स चुकाना भी हमारी जिम्मेदारी है। गांव में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वे सार्वजनिक नल से निःशुल्क पानी भर सकते है, लेकिन जो लोग टैक्स चुकाने में सक्षम है, उन्हें टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चर्चा में शामिल लोगों ने गांव में टैक्स प्राप्त करने की जिम्मेदारी जल तदर्थ समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को दी गई। इसके बाद उनके द्वारा जलकर की राशि एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप गांव के 143 परिवारों ने जनवरी से मार्च माह तक की कुल 3 महीनों जलकर राशि का भुगतान किया। इस तरह ग्राम पंचायत को जलकर के रूप में 43 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई।

इस तरह पलानीमाल के लोगों ने यह साबित किया है कि यदि लोग पंचायत के कार्यों में भागीदारी करते हुए टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी निभाएं तो गांव के सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

खास बातें

- पलानीमाल गांव में नल—जल योजना लागू थी, लेकिन लोगों द्वारा जलकर नहीं चुकाने के कारण उसके प्रबंधन की दिक्कत हो रही थीं।
- लोगों की मांग थीं कि नल—जल योजना से निःशुल्क पानी मिलना चाहिए। लेकिन पंचायत के पास बिजली और मेन्टेनेन्स के लिए बजट नहीं था।
- समर्थन के कार्यकर्ता ने इस विषय पर ग्रामवासियों से विस्तार से चर्चा की। उन्हें स्थानीय स्वशासन में लोगों की भागीदारी एवं जिम्मेदारी के बारे में बताया गया।
- लोगों को अहसास हुआ कि यदि वे जलकर नहीं चुकाएंगे तो यह व्यवस्था बंद हो जाएगी।
- जल तदर्थ समिति एवं सरपंच तथा सचिव ने घर—घर जाकर ग्रामवासियों की सहमति से जलकर एकत्र करने का प्रयास किया।
- लोग जलकर देने के लिए तैयार हुए। 143 परिवारों ने पिछले तीन महीनों का जलकर चुकाय। इससे कुल 43000 रूपए एकत्र हुए।
- अब यहां नल—जल योजना सुचारू रूप से चल रही है।

योजनाओं पर संवाद और जागरूकता

सीहोर। सामाजिक—आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जाती है। लेकिन जानकारी और जागरूकता के अभाव में कई जरूरतमंद लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। अतः इस दिशा में जागरूकता के प्रसार की जरूरत महसूस होती रही है। इसी जरूरत को देखते हुए समर्थन द्वारा मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी प्रसारित की जा रही है। साथ ही योजनाओं तक लोगों की पहुंच बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ज्यादातर जानकारियां आनलाईन उपलब्ध है और कई योजनाओं के लिए आनलाईन आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकते है। साथ ही आवेदन पर हुई कार्यवाही भी आनलाइन देखी जा सकती है। किन्तु ज्यादातर लोग आनलाइन प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते है। अतः समर्थन द्वारा गांव के युवाओं को आनलाईन प्रक्रिया का प्रशिक्षण देकर योजनाओं की जानकारी हासिल करने हेतु सक्षम बनाया गया। इसके साथ ही समर्थन द्वारा गांव—गांव में योजनाओं पर संवाद कायम कर उनके क्रियान्वयन की स्थिति का भी आकलन किया जाता है। ओरेकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत पिछले दिनों सीहोर जिले के 10 लोगों की समग्र आईडी नंबर की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आनलाईन आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। साथ ही ग्राम पंचायत कृष्णाकल्याणपुर में एक दिवसीय जागरूकता कैम्प का आयोजिन किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मातृत्व वंदन योजना की जानकारी दी गई। इसके अलावा समग्र आईडी, पेंशन आदि की जानकारी दी गई।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

खेल खेल में सीख रहे पोषण व स्वास्थ्य

सामुदायिक जागरूकता के लिए खेल के माध्यम से दी जा रही जानकारी

राहूल निगम द्वारा

पन्ना। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में यहां विभिन्न कार्यक्रमों व प्रयासों का सतत् संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ गैर शासकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे समुदाय को पोषण व स्वास्थ्य के प्रति सजग व जागरूक किया जा सकें।

जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था समर्थन द्वारा यूनिसेफ के सहयेाग से इस दिशा में सतत् प्रयास किया जा रहा है। समर्थन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय कर पन्ना जनपद पंचायत के अर्न्तगत 20 पंचायतों के 50 गांवों के कुपोषित बच्चों को संजीविनी अभियान के अन्तर्गत प्रतिमाह अतिरिक्त पूरक पोषण आहार प्रदान करने व चिन्हित परिवारों के घरों में पोषण वाटिका स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

जानकारी

यह सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोनाकाल में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के काम शुरू किए गए है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा और भी कई निर्देश जारी किए गए, जिनमें मनरेगा के अंतर्गत वन क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य, मशीनों का उपयोग आदि जरूरी है। प्रत्येक ग्रामवासी के लिए यह जरूरी है कि उसे इन निर्देशों की जानकारी हो। अतः सरकार द्वारा पिछले माह जारी निर्देशों की जानकारी यहां प्रस्तुत की गई है।

मनरेगा में मशीनों के उपयोग संबंधी दिशा निर्देश

भोपाल। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत रोजगार के लिए ऐसे निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिससे गांव में अधोसंरचना का निर्माण हो तथा जल, जमीन, जंगल का संरक्षण और आजीविका के स्त्रोत विकसित हो सके।

आमतौर पर मनरेगा के कामों में मशीनों के उपयोग की मनाही है। किन्तु कुछ कार्यों में मशीनों की जरूरत पड़ती है। अतः मध्यप्रदेश शासन द्वारा 8 फरवरी को जारी आदेश में मनरेगा के अंतर्गत मशीनों के उपयोग संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा विशेष निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं, ताकि वे ही कार्य मशीनों से किए जा सके, जो मानव श्रम द्वारा किया जाना संभव नहीं हो या मुश्किल हो। साथ ही मशीनों से काम करवाने पर मजदूरों का काम प्रभावित नहीं हो।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जारी वार्षिक मास्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7 के पैरा 7.1.3 में मशीनों के उपयोग के संबंध में निर्देश दिए गए है। इसी पर आधारित निर्देश मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि

स्थानीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग, जन संसाधन विभाग, नर्मदा विकास प्राधिकरण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि विभागों में पंजीतृत ठेकेदारों की सूची एवं उनके पास मशीनों की उपलब्धता एवं उनके मोबाईल नंबर की जिला स्तर पर सूची तैयार की जाए एवं इस सूची को जनपद स्तर पर ग्राम पंचायातें, उपयंत्री, सहायक यंत्री तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराया जाए। उपयंत्रियों के 3 क्लस्टर लगभग 25-30 ग्राम पंचायतों हेतु स्व सहायता समूहों का ब्लाक स्तरीय संगठन हेतु उनके स्वयं के स्त्रोत से या बैंक से ऋण लेकर मशीनों का क्रय कराया जाकर जनपद पंचायत के अंतर्गत 2-3 सेल तैयार करवाए जाए। मशीनों की सूची तथा सम्पर्क मोबाईल नंबर जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों, उपयांत्रियों, सहायक यंत्री तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाए। मशीनों के सेल से मशीनरी किराये पर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। मशीनरी के उपयोग एवं अवधि का सत्यापन उपयंत्री व सहायक यंत्री द्वारा कार्य की मात्रा अनुसार किया जाएगा। इस सत्यापवन के बाद ही एफटीओ के माध्यम से मशीन प्रदायकर्ता वेण्डर को उसके खातें में भुगतान किया जाएगा। **(शेष पृष्ठ 7 पर)**

खास बातें

- ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर उन ठेकेदारों की सूची तैयार की जाए, जिनके पास मशीने उपलब्ध हो और जो लोक निर्माण विभाग, नर्मदा विकास प्राधिकरण एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना में पंजीकृत हो। यह सूची जनपद पंचायत को के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उपयंत्री व सहायक यंत्री को उपलब्ध करवाई जाएं।
- स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर व ब्लाक स्तरीय संगठनों से मशीने क्रय करवाकर उनकी सूची एवं मोबाइल नंबर जपपद पंचायत को उपलब्ध करवाए जाएं।
- मशीनरी के उपयोग एवं अवधि का सत्यापन उपयंत्री व सहायक यंत्री द्वारा कार्य की मात्रा अनुसार किया जाएगा। इस सत्यापवन के बाद ही एफटीओ के माध्यम से मशीन प्रदायकर्ता वेण्डर को उसके खातें में भुगतान किया जाएगा।
- जिन कार्यों में मशीनों का उपयोग किया जाये, उनकी सूचना स्थानीय भाषा में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। इसमें अंतर्गत मशीनों पर व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि एवं उपयोग किए जाने के उद्देश्य लिखे हो।
- मशीनों से किए जाने वाले कार्यों का भी अन्य कार्यों की तरह ही सोशल ऑडिट कराया जाना जरूरी होगा।

मनरेगा के अंतर्गत हर हाथ को काम अभियान प्रारंभ

मनरेगा स्थापना दिवस 2 फरवरी से मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार देने हेतु अभियान शुरू किया गया। गांव-गांव में लगेगी रोजगार चैपाल

भोपाल। देश में मनरेगा कानून आज से डेढ़ दशक पहले शुरू हुआ था। इसके स्थापना दिवस पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ''हर हाथ को काम'' नाम से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव के सभी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार गांव में जिन श्रमिक परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें भी जॉबकार्ड देकर रोजगार दिया जाएगा। यानी रोजगार की जरूरत वाले प्रत्यैक ग्रामीण परिवार को इस अभियान के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। रोजगार हेतु किए जाने वाले कार्यों में कोरोना से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकाल का पालन करते हुए रोजगार चैपाल लगाने का निर्देश दिया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध करावाया जाएंगा तथा यह

सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जरूरतमंद श्रमिक रोजगार से वंचित न रहे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जून 2021 तक प्रतिदिन 25 से 38 प्रतिशत श्रमिकों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की जा रही है। योजना तैयार करने की प्रक्रिया में ग्रामवासियों को भी शामिल किए जाने का निर्देश दिया गया है। अभियान के दौरान श्रमिकों के बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की जाएगी और जिन खातों में मोबाइल नंबर नहीं है या मोबाइल नंबर बदल गए है, उन्हें अपडेट करवाया जाएगा, ताकि उन्हें मजदूरी भुगतान की जानकारी मिल सकें। इसके साथ ही जिन परिवारों के पास जाब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास पहले जॉब कार्ड थे, लेकिन उनके पलायन करने या अन्य किसी कारण अक्रियाशील हो गए हो, उन्हें फिर से बनाया जाएगा।

इस तरह प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया हर हाथ को काम अभियान के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें जागरूक भी बनाया जाएगा और रोजगार चैपाल के माध्यम से उन्हें मजदूरी की दर, व्यक्ति मूलक कार्य एवं सामुदयिक कार्यो के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा।

खास बातें

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 फरवरी 2021 से ''हर हाथ को काम'' अभियान प्रारंभ किया गया है।
- अभियान के अंतर्गत हर गांवों में रोजगार चैपाल का आयोजन किया जाएगा।
- रोजगार चैपाल में रोजगार की जरूरत वाले श्रमिक परिवारों को रोजगार हेतु आवेदन देने, मजदूरी की दर, व्यक्ति मूलक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों की जानकारी दी जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में जून 2021 तक प्रतिदिन 25 प्रतिशत से 38 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जरूरतमंद परिवार रोजगार से वंचित न रहे।
- एक सप्ताह की पूरी योजना तैयार की जाएगीं। योजना बनाने की प्रक्रिया में ग्रामवासियों को शामिल किया जाएगा।
- श्रमिकों के बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की जाएगी, उसमें मोबाईल नंबर अपडेट किया जाएगा एवं लोगों को रोजगार के अधिकार की जानकारी दी जाएगा।
- जिन श्रमिक परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उनके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे तथा जिनके जॉब कार्ड किसी कारण अक्रियाशील हों गए है, उनके भी नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे।
- सभी गतिविधियों के दौरान कोरोना से सुरक्षा हेतु कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा।

प्रयास से मिली सफलता

अब मुमताज को मिलने लगा है उसके हक कर राशन

आधार में उलझा था राशन, अंगुलियों का निशान न आने से मुमताज को 10 माह से नही मिल पा रहा था राशन

राहूल निगम द्वारा

पन्ना। बेवा मुमताज बानो गुनौर जनपद के महेबा गांव की रहने वाली हैं। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और अपने परिवार के साथ ससुराल रह ही है। 60 वर्षीय मुमताज वृद्धा पेंशन व लोगों के घरों में काम करके अपना भरण-पोषण करती है। लेकिन राशन के लिए आधार अपडेट करवाने की प्रक्रिया में दिक्कत होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा था। मुमताज के पति शेख मौहम्मद का निधन आज से 30 साल पहले ही हो गया था। मुमताज ने हार नही मानी ओर अकेले दम पर अपनी बेटी का पालन पोषण किया। काम की तलाश में मुमताज पन्ना आ गई और लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करने लगी। मुमताज का नाम आज भी महेबा में दर्ज हैं, अति गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली मुमताज अपने गांव महेबा की राशन दुकान में अपने हिस्से का अनाज ले आती थी। परन्तु लॉकडाउन के कारण वे अपने गांव नही जा पाई। जब मोटर चलने लगी और मुमताज गांव गई तो पता चला की आधार अपडेट करवाना होगा तब ही राशन मिलेगा। मुमताज ने पन्ना में सिंडिकेट बैंक में जाकर कई चक्कर लगाये पर वहा कार्यरत आपरेटर ने बताया की आपकी अंगुलियों के निशान नही आ रहे हैं, जिससे आधार अपडेट नही हो रहा

हैं। शायद मजदूरी और उम्र के प्रभाव से अंगुलियों के निशान कमजोर हो गये हैं। यह सुनकर मुमताज अब निराश हो गई। उम्र के इस पड़ाव पर उसके सामने खाद्यान्न की नई चुनौती खड़ी हो गई। अब वह उतना काम भी नही कर पाती। 3-4 घरों में कुछ काम मिला हुआ है, जिससे वे किसी तरह जीवन बिता रही हैं।

समर्थन के कार्यकर्ताओं को जब मुमताज की इस स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने उसे कलेक्टर कार्यायल में जाकर अपनी बात रखने का हौसला दिया। इस हौसले के सहारे वह अपनी व्यथा बताने कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पुहंच गई। जन सुनवाई में मुमताज की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला कार्यालय से संबंधित विक्रेता को राशन प्रदान करने के निर्देश दिये गये है। मुमताज इस त्वरित कार्यवाही से खुश है और उन्हे उम्मीद है कि उन्हे उनके हक का 10 माह का राशन जल्द प्राप्त हो जावेगा।

महिलाओं के प्रयासों से मिला लोगों को उनके हक का पूरा अनाज

जनसुनवाई में शिकायत कर महिलाओं ने रूकवाई खाद्यान्न वितरण की अनियमितता

पन्ना। जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत खजुरीकुडार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानदार द्वारा जनवरी माह में 5 किलोग्राम कम अनाज वितरित किया गया, किन्तु राशन कार्ड में पूरा अनाज दर्ज किया गया।

इस पर समर्थन संस्था द्वारा गठित समुदाय आधारित संगठन ''पंचायत एक्शन टीम'' एवं ''महिला निगरानी समूह'' के सदस्यों द्वारा आपत्ति की गई। किन्तु समुदाय की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए विक्रेता ने यह क्रम जारी रखा और लगातार दो दिनों तक लोगों को कम अनाज देता रहा है। विक्रेता द्वारा लोगों को धमकी भरे लहजे में यह कहकर भगाया गया कि यह विभागीय आदेश है, जहां जाना है जा सकते हो। आपसी बातचीत से समस्या का हल न मिलने पर समिति सदस्यों एवं समुदाय के लोगों द्वारा जनसुनवाई में आवेदन देना सुनिश्चित किया गया। विक्रेता व उसके परिचितों द्वारा महिलाओं पर दबाव बनाकर आवेदन देने से रोकने का भी प्रयास किया गया। लेकिन महिलाओ ने किसी की नहीं सुनी। महिलाओं द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में आवेदन देकर उचित कार्यवाही का निवेदन किया गया। महिलाओं के आवेदन पर कलेक्टर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को तत्काल मौके का निरीक्षण कर मामले की जांच करने का आदेश दिया गया।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

बदलाव की राह पर रोशनी

रोशनी नागले के सफरनामे से मिलती है बदलाव की सीख

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य महात्मा गांधी क्षेत्रीय ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर

कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बैतूल जिले की रोशनी ने कभी समस्याओं के सामने हिम्मत नहीं हारी। रोशन को शुरू से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बीमारी की वजह से अपने माता-पिता खोने वाली 23 वर्षीय रोशन नागले के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थीं। घर की इस परिस्थिति के कारण उसे शिक्षा का अवसर नहीं मिला और बड़ी बहन ने उसकी शादी कर दी। इतनी गंभीर परिस्थिति से जूझने वाली रोशन आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कई महिलाओं की मदद कर रही है। वह घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को भी मदद कर उन्हें हिंसा से मुक्ति दिलवाने के प्रयास कर रही है।

स्व-सहायता से जुड़ाव

वर्ष 2017 में रोशनी अपने गांव के स्व-सहायता समूह से जुड़ी। वह बताती है कि ''मैंने खुद को संभालने के साथ ही अपने परिवार व गांव के लोगों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया। मेरे कार्य और व्यवहार को देखते हुए मेरा चयन आजीविका मिशन द्वारा सामुदायिक स्रोत व्यक्ति रूप में किया गया।'' इस तरह रोशन को समुदाय के बीच काम करने का अवसर मिला। इस काम के दौरान रोशनी ने बैतूल जिले के चिचोली विकासखंड के समूह के गठन का प्रयास शुरू किया। इसके साथ ही सोशल आडिट और ग्रामसभा सशक्तिकरण के काम किए। इसके अंतर्गत लोगों को जानकारी देने एवं स्वशासन के मुद्दे पर जागरूकता लाने का प्रयास किया। वह बताती है कि ''इन अनुभवों से मुझ में आत्मविश्वास बढ़ा और मुसीबतों से संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित हुई। स्व-सहायता समूह से जुड़ने से हमारी बचत बढ़ने लगी और अब हमें दूसरो के सामने हाथ नही फैलाना पड़ता है। अब मै इतनी काबिल हो चुकी हूं कि दूसरो की भी मदद कर सकती हूँ।

महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम के प्रयास

शिव समूह की सदस्य कमला धुर्वे के पति ने उन्हे कई सालो पहले छोड़ दिया था और अभी तक उनकी कोई जानकारी

नही है। वह बहुत परेशान रहती थी, उनके परिवार में 1 बेटा एवं 1 बेटी है जो कि आभी नाबालिग है। उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। 45 वर्षीय कमला धुर्वे के पास आय का कोई साधन नही था। उनका परिवार मानो जैसे टूट कर बिखर ही रहा था। आजीविका मिशन के माध्यम से उन्हें समूह से जोड़ने के कारण उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। अब वह अपने दोनो बच्चो का पूर्ण रूप से पालन करने में समर्थ हो चुकी है।

आपदा सहयोग हेतु मुट्ठी भर चावल एवं सहयोग राशि

गुलाब समूह की बसन्ती धुर्वे की 2 संताने है। बसन्ती दीदी का मानसिक संतुलन ठीक नही है , वह किसी से बात नही कर पाती। इन सदस्यों के परिवार हेतु उनकी अति गरीब स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राम संगठन अध्यक्ष की प्रेरणा से निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी अति गरीब परिवारों का सहयोग ग्राम संगठन करेगा और इस प्रकार ग्राम संगठन के सभी सदस्यों द्वारा एक-एक मुट्ठी चावल जमा किया गया साथ ही उसे स्वस्थ्य एंव स्वच्छता से रहने के लिये प्रोत्साहित किया।

समूह से मिली शक्ति

रोशनी बताती है कि ''समूह से जुडकर मैने 20 रूपये साप्ताहिक बचत शुरू की। समूह से छोट बडे ऋण लेकर अपने परिवार की जरूरते पूरी की। ग्राम में समस्त समूहों के सदस्यों के सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहने एवं समूह में सभी सदस्यों के हितो का ध्यान रखने के कारण मुझे सक्रिय महिला के रूप मे चुना गया। अब सभी समूहों को जानकारी मिल जाती है। जानकारी के सहारे हमारे समूह सदस्यों की परेशानी का निराकरण हम सभी मिलकर करते हैं। जब समूह के सदस्यों की समस्याओं का निपटारा होता है तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। इन सबको खुश होते देखकर हमें भी खुशी मिलता है।

इस तरह से रोशनी नागले के सफरनामा से हम सीख सकते हैं कि, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जहां चाह है वहां राह है। जिस तरह रोशनी ने स्व-सहायता के माध्यम से कार्य करके सफलता पाई है, वैसे ही गांव की और भी महिलाएं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

बाचा बना देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव ङ्क वर्षों से ऊर्जा की कमी की पीड़ा झेलते-झेलते आखिरकार हम ऊर्जा-सम्पन्न बन गये। हमारा गांव बाचा देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बन गया है। यह बताते हुए अनिल उइके बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वे आदिवासी युवा हैं और आदिवासी बैतूल जिले के बाचा गाँव के सौर-ऊर्जा दूत भी हैं

बाचा बना देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव

बैतूल। बाचा गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील की खदारा ग्राम पंचायत का एक छोटा सा गाँव है। बाचा गांव सौर ऊर्जा समृद्ध गांव के रूप में देश भर में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है। यहां की आबादी 450 है। यह मुख्य रूप से आदिवासी बहुल गाँव है। अधिकतर गोंड परिवार रहते हैं।

हमारे गांव के सभी 75 घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग हो रहा है। ङ्क खदारा ग्राम पंचायत के पंच शरद सिरसाम कहते हैं कि हमने बाचा को ऊर्जा की जरूरत में पूरी तरह से आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए संकल्प लिया है। आईआईटी बाम्बे और ओएनजीसी ने मिलकर बाचा को तीन साल पहले ही इस काम के लिये चुना था। इतने कम वक्त में ही हम बदलाव की तस्वीर देख रहे हैं।

धुएं से मुक्ति : सभी 75 घरों में अब सौर-ऊर्जा पैनल लग गये हैं। सबके पास सौर-ऊर्जा भंडारण करने वाली बैटरी, सौर-ऊर्जा संचालित रसोई है। इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हुए महिलाओं ने खुद को प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढाल लिया है। खदारा ग्राम पंचायत की पंच शांतिबाई उइके बताती हैं कि सालों से हमारे परिवार मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे थे। आग जलाना, आंखों में जलन, घना धुआं और उससे खांसी होना आम बात थी। अब हम इंडक्शन स्टोव का उपयोग करने के आदी हो चुके हैं। बड़ी आसानी से इस पर खाना बना सकते हैं। दूध गर्म करना, चाय बनाना, दाल-चावल, सब्जी बनाना बहुत आसान हो गया है। हालांकि हमारे पास एलपीजी गैस है, लेकिन इसका उपयोग अब कभी-कभार हो रहा है। श्रीमती राधा कुमरे बताती है कि पारंपरिक चूल्हा वास्तव में एक तरह से समस्या ही था। मैं अब इंडक्शन स्टोव के साथ सहज हूं। किसी भी समय उपयोग में ला सकते है।

वनधन पर घटता दबाव : वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हीरालाल उइके कहते हैं ङ्क सूर्य-ऊर्जा के दोहन के प्रभाव को गांव से लगे जंगल पर कम होते जैविक दबाव से स्पष्ट मापा जा सकता है। वन सुरक्षा समिति के प्राथमिक कार्यों का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि सभी 12 सदस्य वन संपदा की रक्षा करते है। दिन-रात सतर्क रहते है ताकि कोई भी जंगल को नुकसान न पहुंचाए। हमें अवैध पेड़-कटाई और वन्यजीव शिकार जैसी गतिविधियों के बारे में हर समय सचेत रहना पड़ता है। इससे पहले, महिलाएं ईंधन की लकड़ी के लिए प्राकृतिक रूप से गिरी हुई टहनियों को इकठ्ठा करने के लिए नियमित रूप से जंगल जाती थीं। लकड़ी बीनने जंगल जाना रोजाना का काम था। अब यह रुक गया है और हमें काफी राहत मिली है।

मैं इस गांव का सबसे पुराना मूल निवासी हूं। मैंने करीब से देखा है कि चीजें कैसे बदली हैं। परिवार की आजीविका के लिए तीन एकड़ की खेती पर निर्भर करीब 80 साल के शेखलाल कवड़े याद करते हैं कि कैसे बाचा में कोई सड़क नहीं थी। सफाई नहीं थी। बिजली नहीं थी। आज गांव पूरी तरह से बदल गया है। मैं खुश हूँ कि अपने जीवनकाल में ही बदलाव का आनंद मिल रहा है।

बाचा गांव की सामूहिक भावना को साझा करते हुए, अनिल उइके का कहना है कि बिजली के बिल कम होने से हर कोई खुश है। कारण यह है कि बिजली की खपत में भारी कमी आई है। सौर ऊर्जा संचालित एलईडी बल्ब के साथ घरों की ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से आसानी से पूरा किया जा रहा है।

प्रेरणा स्त्रोत : खदारा ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र कवड़े बताते है कि बाचा ने आसपास के गांवों को प्रेरित किया है। उनका कहना है कि खदारा और केवलझिर गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी रुचि पैदा हुई है। केवलझिर बाचा से सिर्फ 1.5 किमी दूर है, जबकि खदारा 2 किमी है।

मुझे लगता है कि बाचा ने मुझे जिले में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान और सम्मान दिलाया है। जहां भी जाता हूँ लोग सम्मान देते हैं।

इसी तरह की भावना शाहपुर गवर्नमेंट कॉलेज के बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र अरुण कावड़े की भी है। उनका कालेज बाचा से 15 किलोमीटर दूर है। उनके पिता के पास चार एकड़ खेती की जमीन है। यही उनकी जीविका का सहारा है। वे कहते है कि हम धीरे-धीरे सौर ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर हो रहे है क्योंकि ग्रिड द्वारा आपूर्ति की गई बिजली महंगी हो रही है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है।

मुझे गर्व होता है जब मेरे दोस्त मुझसे मेरे घर आने को करते हैं यह देखने कि इंडक्शन चूल्हे के साथ सौर ऊर्जा से चलने वाली रसोई कैसे काम कर रही है। अब तक लगभग सभी दोस्त आ चुके हैं।

बाचा का एक स्थानीय व्यक्ति देवासु सौर पैनलों, इंडक्शन स्टोव, बल्ब कनेक्शन, भंडारण बैटरी और अन्य तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखता है। वह पूछता रहता है कोई समस्या तो नहीं आ रही। छोटी-मोटी शिकायतों पर तुरंत मरम्मत करता है।

सामाजिक व्यवहार में बदलाव : यह सब 2017 में शुरू हुआ जब आईआईटी बॉम्बे ने इस परियोजना के लिए बाचा को चुना। इस बारे में जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के सदस्य रूमी दल्लू सिंह धुर्वे बताते हैं कि आईआईटी बॉम्बे ने सौर पैनल स्थापित करने में मदद की, जबकि तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने इंडक्शन चूल्हे दिए। बाचा के सामाजिक व्यवहार में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सकारात्मक परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है।

उदाहरण के लिए, ग्रामीण तकनीकी अपनाने की झिझक नही रही। वे सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक नजरिया अपना रहे हैं। युवा और भी अधिक उत्साही हैं और पूछते रहते हैं कि सौर ऊर्जा कैसे जीवन को अधिक आरामदायक बना सकती है। पर्यावरण को कैसे बचा सकती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बाचा मॉडल अत्यंत व्यवहारिक और आसानी से अपनाने योग्य है। धुर्वे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्यप्रदेश को हर मामले में आत्मनिर्भर राज्य बनाने की सोच सराहना करते है। उनका मानना है कि यह पहल इस सोच को जमीन पर उतारने में मददगार होगी। अगर बाचा गांव ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है, तो दूसरे गांव भी ऐसा कर सकते हैं।

खास बातें

- बाचा गाँव बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील की खदारा ग्राम पंचायत का गाँव है।
- यह गाँव सौर ऊर्जा समृद्ध गाँव के रूप में देश भर में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है।
- यहाँ की आबादी 450 है , यहां मुख्य रूप से आदिवासी बहुल गाँव है।
- गाँव के सभी 75 घरों में अब सौर-ऊर्जा पैनल लग गये हैं।
- सबके पास सौर-ऊर्जा भंडारण करने वाली बैटरी, सौर-ऊर्जा संचालित रसोई है।
- गाँव की महिलाओं ने इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हुए खुद को प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढाल लिया है।
- वर्ष 2017 में आईआईटी बाम्बे और ओएनजीसी ने मिलकर बाचा गाँव की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने और इसे आत्मनिर्भर गाँव बनाने के लिए चुना था।
- अब यहाँ सौर ऊर्जा संचालित एलईडी बल्ब के साथ घरों की ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से आसानी से पूरा किया जा रहा है।
- हालांकि गाँव में कई लोगों के पास एलपीजी गैस है, लेकिन उसका उपयोग अब कभी-कभार ही हो रहा है।

सही प्रक्रिया से हल हुई समस्या

बाजड़ गांव की सचेत दीदियों के प्रयासों से स्कूल की चाहरदीवारी का निर्माण शुरू हुआ

वासुदेव अकोले द्वारा

बड़वानी। पंचायत राज और स्थानीय स्वशासन में किसी भी समस्या को हल करने हेतु ग्रामवासियों के प्रयास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते है। हमारे आसपास कई समस्याएं होती है और हम सभी उन समस्याओं से अलग-अलग व अक्सर अकेले जूझते हैं।

यदि सभी लोग एक जुट होकर ग्रामसभा में चर्चा करके फैसला लें तो समस्या आसानी से हो सकती है। बड़वानी जिले की राजपुर जनपद पंचायत में शामिल बाजड़ गांव के लोगों ने यह बात साबित की है। उन्होंने गांव के स्कूल चाहरदीवारी की वर्षों पुरानी मांग का ग्रामसभा के माध्यम से हल करने में सफलता हासिल की है।

बाजड़ गांव बड़वानी जिले में दूरदराज के क्षेत्र में बसा है और यहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। राजपुर जनपद क्षेत्र में संचालित सचेत परियोजना के अंतर्गत यहां विभिन्न संस्थाएं सक्रिय है। इसी कड़ी में समर्थन संस्था स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इसके लिए संस्था द्वारा गांव में महिलाओं को सक्रिय भूमिका में आने का अवसर दिया जा रहा है। गांव के मुददों पर सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सचेत दीदी का सम्मानजनक नाम दिया गया है। इन्हीं सचेत दीदियों ने गांव के स्कूल में चहारदीवारी की समस्या को हल करने में सफलता हासिल की।

उल्लेखनीय है कि बाजड़ गांव की प्राथमिक शाला में चारहदीवारी नहीं है। चाहरदीवारी नहीं होने से स्कूल के मैदान का कचरा एवं गंदगी से बचाव मुश्किल हो गया था। बच्चे भी यहां खेल—कूद नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों तथा गांव के लोग चाहते थे कि स्कूल परिसार में चाहरदीवारी बनाई जाए।

इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा कई बार पंचायत से मांग की गई, किन्तु समस्या हल नहीं हुई। सचेत परियोजना के अंतर्गत सक्रिय सचेत दीदियों को प्रशिक्षण में बताया गया था कि इस समस्या को प्रक्रिया के तरह हल सकते हैं। इसके लिए ग्राम विकास योजना में स्कूल की चाहरदीवारी निर्माण को शामिल करना जरूरी है। सचेत दीदियों ने ग्रामसभा में चाहरदीवारी निर्माण का मुद्दा रखा और कहा कि ग्राम विकास समिति द्वारा इस गांव की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करवाया जाए। सचेत दीदियों की मांग पर ग्रामसभा में प्रस्ताव होने के बाद ग्राम विकास समिति द्वारा इसे ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्कूल की चाहरदीवारी निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इससे ग्रामवासी बहुत खुश हैं और उनका हौसला बढ़ गया है।

बाजड़ की यह कहानी हमें संदेश देती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया अपनानी होती है। यदि हम प्रक्रिया के तरह उस पर कार्यवाही करें तो समस्या को हल करना आसान होता है।

अन्य राज्यों से

महिलाओं ने बनाया गांव को नशामुक्त

झारखंड की राजधानी रांची जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर ओरमांझी ब्लॉक के टुंडाहुली पंचायत के दो गांव आरा और केरम में 110 घर हैं। जिसमें लगभग 800 लोग रहते हैं। यह गांव पूरी तरह नशे से मुक्त है।

रांची। यहां से लगभग 27 किलोमीटर दूर ओरमांझी ब्लॉक के टुंडाहुली पंचायत के दो गांव आरा और केरम में 110 घर हैं। जिसमें लगभग 800 लोग रहते हैं। गांव में मनरेगा की मेड सीमा देवी बताती हैं, 'एक साल पहले तक हमारे गांव के लोगों के दिन की शुरूआत कच्ची शराब से होती थी। सुबह से शाम तक हड़िया या कच्ची शराब पीकर नशे में पड़े रहते थे। यहां तक कि महिलाएं भी शराब पीने लगी थीं।

झारखंड के इस गांव के लोग लकड़ी बेचकर और मजदूरी करके जितना कमाते उतना नशे में खर्च कर देते थे। गांव के हालात बहुत खराब थे। 'उन्होंने खुश होकर कहा' ,इस नशे को खत्म करने के लिए समूह की दीदी और गांव के कुछ समझदार लोगों ने बैठक की। एक साल लगातार इन लोगों को समझाने के बाद गांव नशामुक्त बन पाया है। हड़िया बनाने वाले हर घर के बर्तनों को इकट्ठा करके उन्हें बेच दिया गया और उस पैसों को गांव के विकास के लिए रखा गया है। सीमा देवी सखी मंडल की एक सदस्य हैं। यहां कुल आठ स्वयं सहायता समूह चलते हैं, जिसमें 98 महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं सामूहिक बचत तो करती ही हैं साथ ही गांव के विकास में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं।

आठ समूह की महिलाओं ने न केवल नशाबंदी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि गांव को स्वच्छ रखने के लिए हर दिन झाड़ू भी लगाती हैं। हर समूह की महिलाओं ने बांस के दो-दो कूड़ेदान बनाए, जिससे कूड़ा इधर-उधर न फेंका जाए और जिससे पूरा गांव स्वच्छ दिखे। केरम गांव के ग्राम प्रधान रामेश्वर बेड़िया बताते हैं, 'हमारे गांव में एकजुटता हमेशा से थी। सिर्फ नशा की वजह से पूरे गांव का माहौल खराब था। महिला-पुरुष दोनों शराब पीते थे। मनरेगा के आयुक्त गांव में आए और उन्होंने गांव को नशामुक्त करने की बात कही। गांव में नशे की वजह से परेशान तो हर कोई था लेकिन सब इसके आदी हो चुके थे। बच्चों का खानपान, पढ़ाई-लिखाई पर किसी का ध्यान नहीं था। महिलाएं घर में कच्ची शराब बनाती थीं जिससे उन्हें भी शराब की लत लग गई थीं। ग्राम प्रधान ने कहा,' नशाबंदी के लिए कुछ समझदार लोग आगे आए और धीरे-धीरे कुछ लोगों ने शराब पीना छोड़ा। ये संख्या लगातार बढ़ती गयी और यह राज्य का पहला नशामुक्त गांव बना।

आरा-केरम गांव झारखंड राज्य का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरह से नशामुक्त गांव है। गांव को आदर्श बनाने और नशामुक्त करने के लिए गांव के लोगों ने मिलकर विकास की गाथा लिखी है। इस गांव में कुछ-कुछ दूरी पर बांस से बने देसी तरीके के कूड़ेदान रखें हैं, जिसमें हर कोई कूड़ा डालता है। दीवारों पर नशामुक्त और प्रेरक बातें लिखी हैं। एक जगह कई सारे बोर्ड लगे हैं, जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा है, जिससे गांव में योजनाओं को लेकर पारदर्शिता रहे। एक बोर्ड में नव जागृति समिति आरा, केरम गांव के लोगों ने खुद के कुछ नियम बनाए हैं। जिसमें लिखा है कि श्रमदान, नशामुक्त, खुले में शौचमुक्त, चराई बंदी और कुल्हाड़ी बंदी। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन नियमों का पालन गांव में हर कोई करता है। नशामुक्त होने पर गांव को एक लाख रूपए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी गई है।

नदी पुनर्जीवन योजना से रूपारेल नदी को मिलेगा नया जीवन

60 चेक डेम से बढ़ेगा 800 एकड़ जमीन का जल स्तर

खरगोन। जिले के झिरन्या क्षेत्र में स्थित रूपारेल नदी को नया जीवन देने का प्रयोग नदी पुनर्जीवन योजना से सम्भव हो सकेगा। भगवानपुरा और भीकनगांव तहसील के इस वृहद क्षेत्र में 60 चेक डेम बनाए जाएंगे, जिससे 800 एकड़ जमीन का जल स्तर बढ़ेगा। 4 -5 वर्षों में यह क्षेत्र हरा-भरा होकर लहलहाने लगेगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा।

उल्लेखनीय है कि नदी पुनर्जीवन की यह तकनीक भगवानपुरा विकासखंड के ग्राम दाऊदखेड़ी की हनुमान पहाड़ी पर मूर्तरूप ले रही है, जो जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर है। 32 लाख की लागत वाली इस योजना में पानी झिरन्या तहसील की रूपारेल नदी में डालकर ग्रामीणों के सूखे खेतों की प्यास बुझाई जाएगी। दाऊदखेड़ी के सरपंच श्री भंगड़ा बारेला और सचिव श्री मुकेश गोलकार ने कृषक जगत को बताया कि यहां 1250 फलदार और छायादार पौधे लग चुके हैं। 60 चेक डेम के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 11 चेक डेम बन चुके हैं। बारिश का पानी इन पौधों की सिंचाई के साथ ही जल स्तर भी बढ़ा रहा है। उपयंत्री श्री अमित धवल और रोजगार सहायक श्री परशुराम गंधारे ने कहा कि ट्रेंच खुदाई, सीपीटी निर्माण,गंटूर ट्रेंच पितृ पर्वत पर कार्य निर्माणाधीन है, जिसमें मनरेगा के तहत करीब 200 मजदूरों को सतत रोजगार मिल रहा है। चार साल बाद जब 60 चेक डेम पूर्ण हो जाएंगे तो जल स्तर बढने से भगवानपुरा और भीकनगांव क्षेत्र की 800 एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी और क्षेत्र लहलहा उठेगा।

मध्यप्रदेश का मनरेगा का वार्षिक लक्ष्य बढ़ कर हुआ 33 करोड़ मानव दिवस

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश का वार्षिक लेबर बजट रिवाइज कर 33 करोड़ मानव दिवस का किया है। मनरेगा अंतर्गत अब प्रदेश में 33 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य हो गया है, जिसे 31 मार्च 2021 तक पूरा करना होगा। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में कोराना काल में मनरेगा श्रमिकों को हर हाथ को काम मुहैया कराकर इस लक्ष्य को माह सितम्बर 2020 में प्राप्त कर लिया था। जिसे भारत सरकार ने पुनरीक्षित कर 28 करोड़ 50 लाख मानव दिवस कर दिया था। प्रदेश द्वारा 28 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के लक्ष्य को 25 जनवरी 2021 तक हासिल कर लिया। मध्यप्रदेश में 18 फरवरी की स्थिति में 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस सृजित हो चुके है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ गुरूवार को आयोजित हुयी वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश में मनरेगा के पूर्व लक्ष्य 31 करोड़ मानव दिवस को को संशोधित करते हुए 33 करोड़ मानव दिवस कर दिया है। दो करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य बढ़ जाने से प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को जहाँ रोजगार के अतिरिक्त अवसर मुहैया होंगे वहीं मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को 380 करोड़ रूपये मजदूरी के रूप में अतिरिक्त प्राप्त होंगे। प्रदेश में मनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण जॉब-कार्डधारी परिवारों को हर हाथ को काम मुहैया कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 अंतर्गत 52 लाख 47 हजार परिवारों के 98 लाख 79 हजार श्रमिकों को 30 करोड़ 63 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। कोविड काल में मनरेगा अंतर्गत सृजित मानव दिवस योजना प्रारंभ से अब-तक के वर्षों में रिकार्ड सर्वाधिक है। मनरेगा के तहत कोविड काल, वर्ष 2020-21 में 6 लाख 45 हजार हितग्राही मूलक और सामुदायिक कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में 6 लाख 74 हजार कार्य प्रगतिरत हैं।

कोरोना के दौर में भी जारी है कागदीपुरा के बच्चों की पढ़ाई

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करना आसान नहीं है। आदिवासी अंचल में जिन लोगों के पास में खाने-पीने के मूलभूत साधनों की कमी है वहां पर स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट की फास्ट स्पीड को लेकर कई प्रश्न खड़े होते है। इस दशा में कागदीपुरा गांव के एक शिक्षक ने बच्चें को मोबाइल की मजबूरी से दूर करके पढ़ाई जारी रखने का तरीका निकाला।

धार। कोरोना के दौरान में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस दशा में धार जिले के एक शिक्षक के दिशा निर्देशन में कई युवा मोहल्ले-मोहल्ले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं। मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य धार जिले के नालछा विकासखंड के कागदीपुरा के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुभाष यादव ने पिछले वर्ष गर्मी की छुट्टी नही मनाई, बल्कि् लाकडाउन में जब कई शिक्षक अपने घर पर बैठे रहे, वहीं कागदीपुरा में ये शिक्षक ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए नई-नई कोशिश में जुटे हुए हैं। सुभाष के दिशा निर्देशन में कई और युवा आगे आये हैं जो बच्चों को रोजाना एक घंटे निशुल्क पढ़ा रहे हैं। सुभाष यादव ने बताया, 'हम ऐसे युवाओं की खोज में लगे हैं जो रोज एक घंटे का समय निकालकर अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा सकें। आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल से पढ़ाई कराना संभव नहीं है। इनके पास न हाई स्पीड इन्टरनेट डेटा है और न ही सबके पास स्मार्ट फोन। कुछ युवा अब जगह-जगह कुछ-कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं।'

मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि बच्चों का जो नुकसान हुआ है, वह किसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा हो सके। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करना आसान नहीं है। आदिवासी अंचल में जिन लोगों के पास में खाने-पीने के मूलभूत साधनों की कमी है वहां पर स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट की फास्ट स्पीड को लेकर कई प्रश्न खड़े होते है। पढ़ाई कार्य में युवाओं को मदद करने वाले रंजीत पटेल का कहना है, 'शासकीय शिक्षक का जुनून देखकर हमें भी लगता है कि हमें भी अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। सर ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घर पर ही 8 से 10 बच्चे एकत्रित हो जाते हैं रोजाना इनको एक घंटे का समय देकर पढ़ा रहे हैं।' कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आने वाले समय में कब स्कूल खुलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सुभाष यादव के दिशा निर्देशन में कुछ युवा इन दिनों एक घंटे का समय निकालकर कागदीपुरा गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुभाष यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में कई व्यापक स्तर पर प्रयोग किए हैं। उसी का नतीजा है कि आज वे मध्यप्रदेश में ख्यात शिक्षक हैं।

गाँव के एक युवा गजानंद परमार बताते हैं, 'हमारे गांव के बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े रहें तो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में स्कूल खोलने में क्या परेशानी आएगी और किस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है कि इस तरह के प्रयोग से हम हमेशा के लिए बच्चों की हित की बात कर सकें।' शासन के निर्देशानुसार मोबाइल पर सामग्री दी जा रही है। लेकिन व्यावहारिक रूप में यह एक भरा कदम है। वजह यह है कि बच्चों के माता-पिता के पास में बहुत ही उच्च गुणवत्ता के एंड्रॉयड फोन नहीं हैं, जिससे की डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा सके। इसके अलावा कई गांव ऐसे हैं, जहां पर इंटरनेट कनेक्शन की समस्याएं हैं। साथ ही जो लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल डाटा का अच्छा वाला पैकेज उपयोग करने में सक्षम हों।

मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों में पलायन से लौटी महिलाओं ने मनरेगा में संभाला काम

भोपाल। मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और आदिवासी बाहुल्य तीन जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर में इन दिनों महिलाएं पसीना बहा रही हैं। इन तीन जिलों में स्थानीय स्तर पर करीब 37,000 मजदूरों को काम दिया गया, जिसमें महिलाओं की लॉकडाउन के बाद अलग-अलग राज्यों से पलायन करके मध्यप्रदेश लौटी महिलाएं इस भीषण गर्मी में बंजर पहाड़ी को हरा-भरा करने में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और आदिवासी बाहुल्य तीन जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर में इन दिनों महिलाएं पसीना बहा रही हैं। तापमान औसत रूप से 41 डिग्री के आसपास है। इन तीन जिलों में स्थानीय स्तर पर करीब 37,000 मजदूरों को काम दिया जा रहा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी 60 फीसदी है। धार जिले के बोधवाड़ा गाँव की राधाबाई (30 वर्ष) बताती हैं, 'अब काम बंद है अगर कमाएंगे नहीं तो खायेंगे क्या? शहर में कोई रोजगार नहीं मिला तो गाँव आ गये। घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं मेहनत करेंगे तभी इनका पेट भर पायेंगे।' राधाबाई की तरह आदिवासी बाहुल्य तीन जिलों की 60 फीसदी महिलाएं मनरेगा के काम में जुट गयी हैं। इस समय मनरेगा के तहत जो भी काम दिए

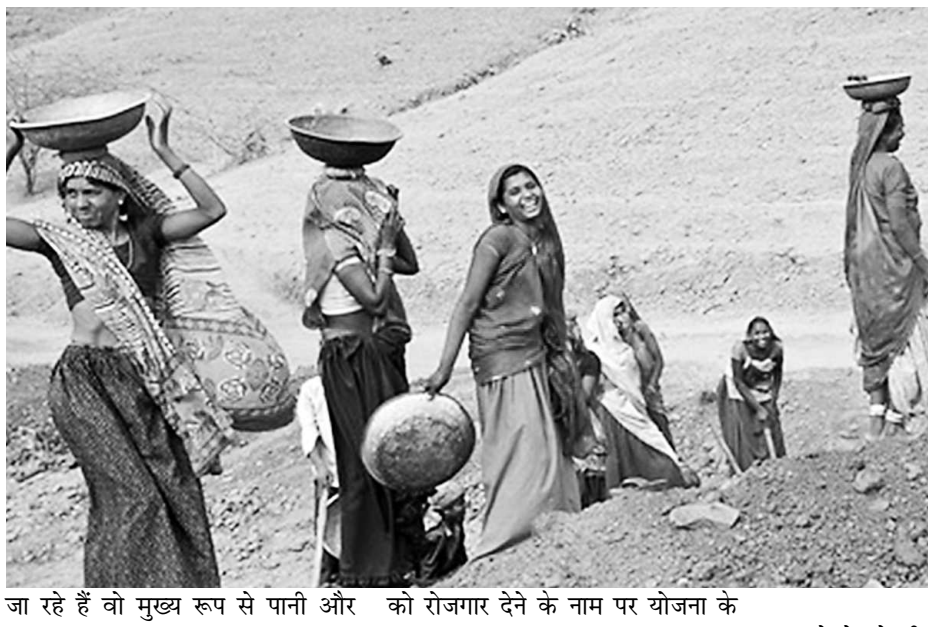

जा रहे हैं वो मुख्य रूप से पानी और पर्यावरण से संबंधित है। इसमें बंजर पहाड़ियों को हरा-भरा करने के लिए कंटूर ट्रेंच निर्माण से लेकर मेढ़ बंधान और कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र को पानीदार बनाएंगे। इस पानीदार काम में महिलाओं की अपनी महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका है। 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच में महिलाएं जमकर पासीना बहा रही हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के शेष काम को पूरा करने का जिम्मा भी इनके ऊपर है। ऐसे में मजदूरों को रोजगार देने के नाम पर योजना के तहत काम हो रहा है। निर्माण काम में भी महिलाएं आगे निकल कर आयी हैं। महामारी के इस दौर में ये घर बनाने का काम पूरा कर रही हैं। धार जिला के जनपद पंचायत सरदारपुर के सहायक परियोजना समन्यवक एसएस भाटी बताते हैं, 'इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में काम कर रही है। बीते सालों में हमें स्थानीय स्तर पर मजदूर डोंडी पिटवाने (सूचना देना) के बाद भी नहीं मिला करते थे। इस बार तो केवल सामान्य सूचना पर ही ग्रामों में लोगों ने काम पर आना शुरू कर दिया है। हमें हर रोज नए जॉब कार्ड बनाने के लिए भी काम करना पड़ रहा है।' लॉकडाउन के वजह से ये आदिवासी मजदूर गुजरात से पसीना बहाते करीब एक लाख पांच हजार मजदूर अपने गाँव को वापस आ गये। ये मजदूर बीते कुछ सालों में गुजरात के शहर की गंदी बस्तियों और तंग गलियों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये भी पढ़ें-गुजरात से वापस आए मजदूर बोले- 'अपने पैसों का टिकट भी लिया और खाने-पीने को भी कुछ नहीं मिला' सुल्तानपुर गाँव की संतोषी ने बताया, 'गाँव में काम आसानी से मिल रहा है। लेकिन मजदूरी बहुत कम है। शहर में एक दिन का 500 रूपये तक कमा लेते थे लेकिन यहाँ 190 रूपये ही मिल रहे हैं। पति भी मशीन चलाकर अच्छा पैसा कम लेता था लेकिन अब तो सबकुछ बंद है। यहाँ मजदूरी एक तिहाई हो गई है।' 'बैठने से तो अच्छा है कमसेकम यहाँ काम तो मिल रहा है। अभी सब लोग बंजर पार्टी में ही काम कर रहे हैं। कम मजदूरी से फर्क तो पड़ता है लेकिन क्या करें जैसे-तैसे पेट भर रहे हैं,' संतोषी ने लॉकडाउन में काम मिलने का संतोष जताया। गाँव वापस लौटने पर इनके सामने रोजी-रोटी का बुरा संकट था। गाँव में मनरेगा और निर्माण का काम शुरू होते ही कुछ मजदूरों को काम मिल गया है। ये भी पढ़ें-लॉकडाउन से छिन गया पूरे गाँव का रोजगार, अब किसी के पास कोई काम नहीं बचा है ग्राम पंचायत सहायक मोहन भाई बताते हैं, 'ग्राम पंचायत माछलिया में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं। ये अब अपने मूल ग्राम में ही रह रहे हैं। इनको हमने रोजगार दिया है। बाहर से आने वाले मजदूरों को काम मिलने से वे यहां पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।' पलायन करके गाँव लौटे मजदूरों के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है, ऐसे में मध्यप्रदेश के इन जिलों में मजदूरों को मिला काम एक उम्मीद है। 'पति, बच्चों के साथ गुजरात से अपने गाँव आ गये। खेती दो बीघा है, इतनी जमीन में तीन परिवारों का खर्चा नहीं चल सकता। खेती से थोड़ा बहुत अनाज मिल जाएगा, दूसरे खर्चों के लिए गाँव में अब मजदूरी मिल गयी है,' भूरी वास्केल मनरेगा में मिली इस मजदूरी से खुश हैं।

38 नई नल जल योजनाओं को मंजूरी

मई में 15 गांवों की 22 हजार 500 आबादी को पानी

सीहोर। गर्मी आते ही शहरों से लेकर गांवों तक पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शहरों में टैंकर एवं अन्य कई माध्यम से यह समस्या हल हो जाती है, लेकिन दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रें में पानी की समस्या आसानी से हल नहीं हो पाती। अतः सरकार द्वारा पानी की समस्या को हल करने के विशेष योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में सीहोर जिले के हर गांव में घर—घर पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि नल—जल योजनाओं से जिले के हर गांव में पानी पहुंचाने की योजना है। अभी 179 योजनाओं का काम होना है जिनमें से 70 का काम चल रहा है जिनका 20 से 40 फीसदी काम हो चुका है। 15 गांव ऐसे हैं जहां मई में लोगों को पेयजल मिल जाएगा। यानी इस साल गर्मी में 22 हजार 500 की आबादी को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

इसके साथ 38 और नई योजनाओं को मंजूरी मिल गई है जिनका काम 15 दिन में शुरू होने वाला है। जिले के 1034 गांवों के लोगों को नलजल से 2 लाख 32 हजार 748 परिवारों को पानी पिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पहले फेस में 255 नलजल योजनाओं का प्लान तैयार किया है। इनमें से 179 को स्वीकृति मिल गई है। इनमें 49 वे योजनाएं हैं जो बंद पड़ी थीं।

जिले में अभी तक 309 नलजल योजनाएं थीं जिनमें कई लंबे समय से बंद पड़ी थीं। इनके बंद होने के पीछे के कई कारण थे लेकिन जो प्रमुख कारण रहता था वह यह कि अधिकांश लोग जलकर देते नहीं थे और बिजली कनेक्शन कट जाता था। कई बार मोटर पंप जल जाने से मरम्मत के लिए पंचायत के पास पैसे नहीं होते थे और योजना बंद हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

योजना में अब यह है बदलाव

पहले योजना के रख रखाव के लिए लोग जलकर नहीं देते थे और पैसे के अभाव में योजना बंद हो जाती थी। अब योजना में उस गांव के लोगों को जोड़ा गया है। अब गांव में पेयजल एवं स्वच्छता समिति बनेगी। समिति का जब गठन किया जाएगा तो इसमें गांव के प्रत्येक वार्ड से एक पुरुष और एक महिला को समिति में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और अन्य कार्यकारिणी बनेगी।

10 प्रश राशि ग्रामीणों को जुटानी होंगी

जो भी नलजल योजना होगी उसकी जल वितरण प्रणाली पर जो खर्च होगा उस राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा गांव के लोगों को एकत्रित करना होगा।

15 दिन बाद शुरू होगा काम

पहले फेस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जिले के 1034 गांवों में 25 फीसदी गांवों के लिए योजना तैयार की है। वर्ष 2021 के लिए 255 गांवों के लिए योजना बनाई जिसमें से 179 को स्वीकृति मिल चुकी है। शुरू में 70 के कार्य आदेश हुए। 109 जो बची उनमें से भी अब 38 को मंजूरी मिल चुकी है। इनका काम 15 दिन बाद शुरू हो जाएगा।

41 हजार दिए जाएंगे कनेक्शन

पहले फेस में जो योजनाएं पूरी होंगी उनमें 41 हजार घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे करीब 2 लाख 5 हजार की आबादी को पानी मिलेगा।अभी मई में 15 गांवों की योजनाओं को शुरू कराया जाएगा। जहां पर एक फेस का काम पूरा हो जाएगा तो वहां सीधे कनेक्शन जोड़कर पानी दिया जाएगा जब तक टंकी नहीं बन जाती है।

किन कारणों से होती है योजनाएं बंद ?

- लोग समय पर अपना जलकर जमा नहीं करते हैं। कुछ लोग देते हैं जिससे कुछ समय तक योजना चलती है।
- पंचायत के पास पैसा नहीं होने से बिजली का बिल जमा नहीं हो पाता है और बिजली कट जाती है।
- मोटर पंप खराब होने की दशा में इसे ठीक कराने के पैसे नहीं रहते हैं
- गांव में सड़कों का निर्माण होने के समय पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसके बाद तो इनकी ना तो मरम्मत हो पाती है और ना ही बदला जाता है।
- 25 साल से अधिक पुरानी योजना होने से भी कुछ जीर्णशीर्ण स्थिति में पहुंच गईं।

सभी गांवों में 2024 तक पहुंचाना है पानी, 15 गांवों में मई तक देंगे पानी

पूरे जिले के गांवों में वर्ष 2024 तक पानी देना है। इसके लिए जून 2021 तक 179 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। पहले चरण में 41 हजार से अधिक नल कनेक्शन देकर 2 लाख 5 हजार की आबादी को पानी मुहैया कराया जाएगा। 15 गांवों की योजनाओं को मई माह तक शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

-एमसी अहिरवार,
ईई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

युवाओं के सहयोग से 8 माह से चल रही है मोहल्ला शाला

राहूल निगम द्वारा

पन्ना। कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल बंद हुए तो शहरों में वापस लौटे लोगों को समर्थन संस्था द्वारा मोहल्ले के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए युवाओ ंको प्रेरित किया गया। अब इन युवाओं द्वारा करीब 8 माह से मोहल्लों में स्कूल लगाकर बच्चों केा माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से बचाव हेतु पिछले वर्ष मार्च माह में देशभर में लाकडाउन लगाया गया था। जुलाई माह आते-आते लाकडाउन में कुछ छूट मिली, परन्तु शैक्षणित संस्थान साल भर नहीं खुले। ऐसे में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए ग्राम स्तर पर पढ़े-लिखे युवा साथियों को चिन्हित किया गया। इन युवाओं को प्रेरित कर अपने घर व आसपास के बच्चों को कोविड-19 के बचाव के सभी निर्देशों का पालन कराते हुए पढ़ाई में सहयोग करने का आग्रह किया गया।

ग्राम बिल्हा के निवासी महेन्द्र पटेल भी ऐसे ही एक युवा है। महेन्द्र लाकडाउन के पूर्व पन्ना में रहकर उच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लॉकडाउन लगने के बाद महेन्द्र अपने गांव में ही रह रहे थे।

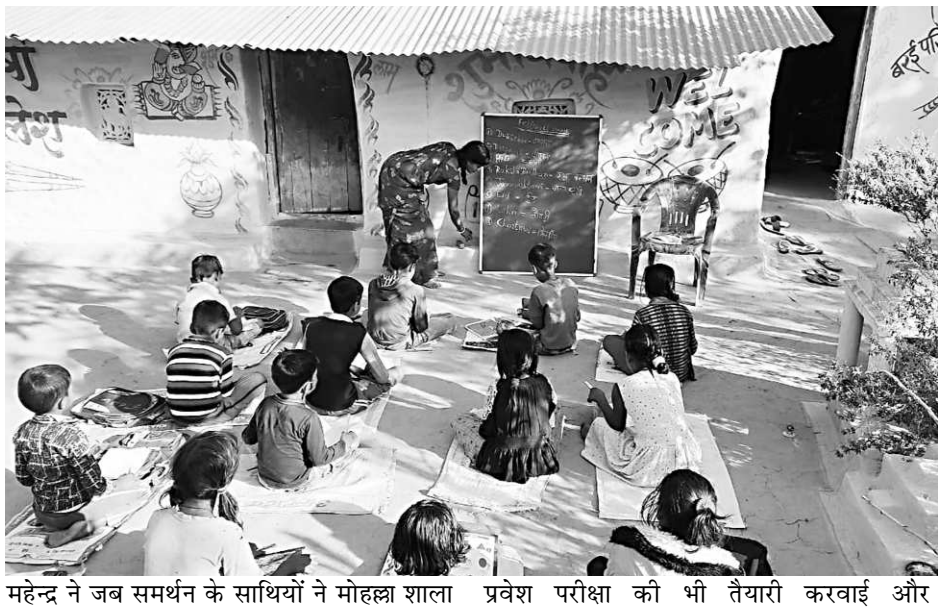

महेन्द्र ने जब समर्थन के साथियों ने मोहल्ला शाला की बात की जाते उन्हें यह काम पंसद आया। महेन्द्र पिछले 8 माह से 50 बच्चों को मोहल्ला शाला के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वही ग्राम रक्सेहा में सुजय भी अपने गांव के 40 बच्चों को पिछले 8 महीनों से लगातार मोहल्ला शाला में पढ़ा रहे हैं। सुजय ने इन बच्चों को नवोदन विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी करवाई और मार्गदर्शन दिया। इन शालाओं में प्रवासी श्रमिक, वंचित परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। समर्थन के प्रयासों से 20 गांवो में युवाओं द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रह है। इन मोहल्ला शालाओं में पढ़ाई के साथ ही गीत, कहानी, चित्रकला जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाती है। इससे बच्चों को पढ़ाई में रूचि बढ़ती है उनकी सीखने की गति भी बढ़ती है।

खास बातें

- कोरोना लाकडाउन से लेकर अब तक स्कूल बंद होने से बच्चों के सामने पढ़ाई का समस्या पैदा हो गया है।
- कोरोना से बचाव के प्रोटोकाल का पालन करते हुए बच्चों के साथ शैक्षणित गतिविधिया का यह अनूठा तरीका समर्थन द्वारा निकाला गया। इसमें गांव के युवाओं द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है।
- समर्थन द्वारा गांव में युवाओं को प्रेरित किया गया कि वे बच्चों की मोहल्ला शाला लगाए और उनमें बच्चों को पढ़ाई।
- 20 गावों युवा पिछले 8 महीनों से मोहल्ला शाला में बच्चों को पढा रहे है।
- मोहल्ला शाला में बच्चों पढ़ाई के साथ ही गीत, कहानी, चित्रकला जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाती है। इससे बच्चों को पढ़ाई में रूचि बढ़ती है उनकी सीखने की गति भी बढ़ती है।

बस्तर जिले का अनूठा माईक स्कूल

भाटपाल पंचायत बनी शिक्षा की मिसाल, कोरोना काल में घर बैठे लाउडस्पीकर से पढ़ाई कर रहे बच्चे

बस्तर। बस्तर जिले के एक छोटे सी पंचायत ने देश भर में कोरोना के संकटकाल में एक मिसाल कायम किया है, जहां लाउडस्पीकर से बच्चे अपने घरों में बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रदेश ही नहीं देश का पहली ऐसा पंचायत है जहां लाउडस्पीकर से बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारें लाख जतन कर रही हैं। पर, बस्तर के वे इलाके जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच सकी है, वहां के लिए यह एक नजीर है।

दरअसल, कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। इसी के तहत बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हैं। हालांकि, लॉकडाउन अब समाप्त हो चुका है, किन्तु स्कूलों को अब भी बंद रखा गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई में काफी रुकावटें आ रही हैं। जिसको देखते हुए बस्तर के भाटपाल पंचायत के सरपंच और पंचायत के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की मदद से एक अनोखी पहल की।

सरपंच ने पंचायत के सभी 8 मोहल्लों में लाउडस्पीकर लगाकर बच्चों की पढ़ाई शुरू करा दी। इसका असर यह हुआ कि अब बच्चे लाउडस्पीकर की आवाज सुनते ही घरों के बाहर निकलकर अपने पढ़ने की जगह पर पहुंच जाते हैं। वे अपने हाथों को सेनेटाइज कर सामाजिक दूरी बनाते हुए पढ़ाई करते हैं।

बच्चों के अनुसार, कई महीनों से स्कूल बंद है और ऐसी स्थिति में पढ़ाई में मुश्किलें आनी लगी थीं। पर, अब उनको पढ़ाई के साथ-साथ अन्य बातों

का ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि लाउडस्पीकर से न केवल विषय से जुड़ी बातें सिखाई जा रही हैं, बल्कि अन्य सामाजिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। इससे अंदरूनी इलाकों के बच्चों का मानसिक विकास भी हो रहा है। लाउडस्पीकर के चालू होते ही बच्चे तो उत्साहित होकर पढ़ने बैठते ही हैं, साथ ही बच्चों के अभिभावक भी उत्साह से लाउडस्पीकर की बातों को सुनते और सीखते हैं।

अभिभावकों का कहना है कि उनके समय में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो उन्हें इंग्लिश का कुछ भी ज्ञान नहीं है। पर जब से पंचायत में लाउडस्पीकर से पढ़ाई शुरू हुई है, तब से उनको भी इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान होने लगा है। साथ ही बच्चे तो पढ़ाई कर सीख ही रहे हैं पर इस नए तरीके से पढ़ाई के शुरू होने की वजह से अभिभावकों में भी खुशी है।

कोरोना संकट काल के बीच बस्तर के भाटपाल पंचायत का यह प्रयोग अपने आप मे मिसाल साबित हो रहा है। जिला प्रशासन ने तो जिले के अन्य पंचायतों में भी इस तरीके से पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। प्रदेश सरकार भी कोरोना संकट को देखते हुए लाउडस्पीकर से पढ़ाई के इस नए तरीके को प्रदेश के अन्य जगहों पर भी लागू करने की तैयारी कर रही है।

मनरेगा के अंतर्गत वन क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश

भोपाल। मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले ज्यादातर कार्य गांवों की राजस्व भूमि में किए जाते हैं। अब वनक्षेत्र में भी मनरेगा के कार्य किए जाने के निर्देश मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में वन भूमि पर मनरेगा कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए है। उल्लेखनीय है कि लाकडाउन और कोरोना के दौर में मनरेगा ही रोजगार का प्रमुख स्रोत है तथा सरकार द्वारा मनरेगा के काम बड़े पैमाने पर शुरू किए गएं इसके लिए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित लेबर बजट तैयार किया गया। इस बजट के अनुसार रोजगार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व भूमि पर कार्य करके पूरा नहीं किया जा सकता। अत: वन क्षेत्र में कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए है। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य का परीक्षित लेबर बजट का 93 प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है तथा हर ग्राम पंचायत में 25 से 38 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग की जा रही है। अत: ग्राम पंचायतों से लगे वन क्षेत्रों में भी मनरेगा का कार्य किया जाएगा, जिनमें ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी होगी। शासन के आदेशानुसार समय सीमा में लेबर बजट की लक्ष्य प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायत श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में नियोजित करने हेतु वन क्षेत्र में काम की योजना बनाएं, ताकि रोजगार की मांग की पूर्ति की जा सके।

वन क्षेत्र में कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं जैसे मिट्टी संरक्षण हेतु कंटूर ट्रेंच, पालाबंदी, गली प्लग जैसे ढांचे बनाए जा सकते हैं। इसी तरह जल संरक्षण हेतु वन क्षेत्र के गुजरने वाली नदियों के पानी को रोकने संबंधी कार्य, छोटे तालाब या तलैया आदि बनाए जा सकते हैं।

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडल: पंकज पांडे, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, सादमा खान, नेहा छावड़ा, राहूल निगम, नारायण परमार, मनोहर गौर, विनोद चौधरी

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713